



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 416]
No. 416]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 30, 1984/भाद्र 8, 1906
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 30, 1984/BHADRA 8, 1906

इत भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1984

का. आ. 862(अ) :—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में फर्टिलाइजर
कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, गोरखपुर यूनिट के प्रबंध-
तंत्र से संबद्ध औद्योगिक विवाद, नियोजकों और उनके कर्मचारियों
के बीच विद्यमान है ;

और उक्त विवाद में राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न अन्तर्गत है और
यह विवाद ऐसी प्रकृति का भी है जिसमें फर्टिलाइजर कारपोरेशन
आफ इंडिया के एक से अधिक राज्यों में स्थित प्रतिष्ठानों
की अभिवृत्ति होने या इस विवाद से प्रभावित होने की सम्भा-
वना है ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त विवाद का राष्ट्रीय
अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन किया जाना चाहिए ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार :—

- (1) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14)
की धारा 7-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, एक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण गठित करती
है जिसका मुख्यालय कलकत्ता में होगा और न्याय-
मूर्ति श्री एम. पी. सिंह को इसका पीठासीन
अधिकारी नियुक्त करती है ; और

- (2) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1-क)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त
औद्योगिक विवाद को न्याय-निर्णयन के लिए उक्त
राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को निर्दिष्ट
करती है ।

अनुसूची

क्या नियोजकों द्वारा प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को 26 दिन का
महीना मान कर अर्जित छुट्टी का नकदीकरण न करना न्यायोचित
और/या वैधानिक है ? यदि नहीं, तो कर्मचारी किस फायदे/
अनुबोध के हकदार है और उनका ब्यौरा क्या है ?

[एल.-51041/22/84-आई. एण्ड ई. (एस. एस.)]

बी. एस. एलावादी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

(Department of Labour)

ORDER

New Delhi, the 29th August, 1984

S.O. 662(E).—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employer of the Fertilizer Corporation of India, Gorakhpur Unit and its workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed.

And whereas the said dispute involves a question of national importance and is also of such a nature that industrial establishments of Fertilizer Corporation of India situated in more than one State are likely to be interested in or affected by the dispute.

and whereas the Central Government is of opinion that said dispute should be adjudicated by National Tribunal.

Now, therefore, the Central Government.—(i) In exercise of the powers conferred by Section 7B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), hereby constitutes a National Industrial Tribunal with Headquarters at Calcutta and appoints Justice Shri M. P. Singh as its Presiding Officer, and

(ii) In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 10 of the said Act, hereby refers the said industrial dispute to the said National Industrial Tribunal for adjudication.

SCHEDULE

Is it correct and/or legal that the employer does not pay earned leave encashment to the employees of the Organisation taking into account the month of 26 days. If not, to what benefit/relief the employees are entitled to and with what details.

[No.L-51041/22/84-I&E(SS)]

V. S. AILAWADI, Jt. Secy.